



हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर



वर्ष:4 अंक:278 पृष्ठ:08 मूल्य:1 रूपये

pathpravah.com

हरिद्वार, रविवार, 12 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के सख्त निर्देशों पर 350 से अधिक सैपलों की जांच, दर्जनों मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के सख्त दिशा-निर्देशों पर उत्तराखंड में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए औषधि विभाग ने बड़ा राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य बाजार में बिकने वाले कफ सिरप की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करना है, ताकि किसी भी प्रकार की हानिकारक या प्रतिबंधित औषधि बच्चों तक न पहुँच सके।

राज्यभर में औषधि विभाग ने मेडिकल स्टोर्स, होलसेल डिपो, फार्मा यूनिट्स और बच्चों के अस्पतालों में औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है। अब तक 350 से अधिक सैपल जांच हेतु लिए जा चुके हैं, जबकि एक दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। कई अन्य को कड़ी चेतावनी भी दी गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 'हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड में ऐसा कोई सिरप न बिके, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बने। यह सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है।'

देहरादून में औषधि विभाग की सघन कार्रवाई

देहरादून में आयुक्त एवं अपर आयुक्त (एफडीए) के निर्देश पर औषधि निरीक्षक मानेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में टीम ने पलटन बाजार, घंटाघर, ऋषिकेश रोड, जॉलीग्रैंट, अजबपुर और नेहरू कॉलोनी क्षेत्रों में मेडिकल



स्टोर्स और थोक विक्रेताओं की जांच की।

निरीक्षण के दौरान बच्चों की सदी-खांसी की कुछ दवाइयाँ अलग से भंडारित पाई गईं, जिन्हें मौके पर सील कर दिया गया और बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। एक मेडिकल स्टोर को बंद किया गया, और 11

औषधियों के नमूने जांच हेतु संकलित किए गए। टीम ने बताया कि SYP. Coldrif, SYP. Respifresh-TR और SYP. Relife जैसी प्रतिबंधित दवाएँ स्टोर्स पर नहीं मिलीं। कार्रवाई औषधि निरीक्षक विनोद जागुड़ी और निधि रतूड़ी की उपस्थिति में हुई।

ऋषिकेश में बड़ी कार्रवाई — सिरप भंडारण पर रोक

औषधि निरीक्षक निधि रतूड़ी के नेतृत्व में टीम ने ऋषिकेश क्षेत्र, राजकीय एसपीएस चिकित्सालय और जॉलीग्रैंट के आसपास मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। कुछ स्टोर्स में बच्चों की सदी-खांसी की दवाइयाँ अलग से रखी मिलीं, जिन्हें तुरंत सील कर बिक्री पर रोक लगाई गई। निरीक्षण के दौरान 6 औषधियों के नमूने गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए। निरीक्षक ने बताया कि अधिकांश मेडिकल स्टोर्स ने शासन के आदेशों का पालन करते हुए प्रतिबंधित सिरप की बिक्री पहले ही बंद कर दी है।

हल्द्वानी, अल्मोड़ा और बागेश्वर में भी अभियान तेज

हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में सात मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई, जहाँ से दो कफ सिरप के नमूने जांच हेतु लिए गए। अल्मोड़ा में एक मेडिकल स्टोर से कफ सिरप का नमूना लिया गया, जबकि बागेश्वर जिले के गरूर क्षेत्र में दो मेडिकल स्टोर्स से बाल चिकित्सा सिरप के दो नमूने संकलित किए गए। सभी विक्रेताओं को शासन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य सचिव की सख्त चेतावनी

स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त (FDA) डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान केवल मेडिकल स्टोर्स और डिपो तक सीमित नहीं है, बल्कि फार्मा कंपनियों और बाल चिकित्सालयों तक विस्तारित किया गया है। डॉ. राजेश कुमार ने कहा, 'प्रत्येक जिले की टीम से प्रतिदिन रिपोर्ट ली जा रही है, और जहाँ भी लापरवाही मिलेगी, वहाँ लाइसेंस निरस्तीकरण सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी।'

स्वास्थ्य मंत्री की अपील — डॉक्टर निभाएँ जिम्मेदारी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य के सभी डॉक्टरों से अपील की कि वे बच्चों के लिए दवाइयाँ लिखते समय विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी स्थिति में प्रतिबंधित सिरप न दी जाए। डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों की यह साझी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की सेहत को सर्वोपरि रखें।

अभियान का नेतृत्व

अभियान का नेतृत्व अपर आयुक्त (एफडीए) ताजबर सिंह जगगी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यभर में यह अभियान चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण औषधियाँ ही उपलब्ध कराई जाएँ।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश: गढ़ा मुक्त हो प्रदेश, समयबद्धता और गुणवत्ता से करें काम



पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों को शीघ्र गढ़ा मुक्त किया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर और सुरक्षित यातायात सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि सड़कें प्रदेश के विकास की रीढ़ हैं, इसलिए इनके रखरखाव और गुणवत्ता पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि अब तक प्रदेश की सड़कों पर 52 प्रतिशत पैचवर्क का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शेष कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समयबद्धता और गुणवत्ता दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सभी जनपदों के प्रभारी सचिवों को अपने-अपने जिलों का नियमित भ्रमण कर जनता से संवाद स्थापित करने और सरकार की विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं

के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं — जैसे सड़कें, पुल और सामुदायिक भवन — का शीघ्र पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि स्थानीय जनता को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त पुलों के शीघ्र पुनर्निर्माण और नए पुलों के निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और सजगता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

भारत को कृषि उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि निर्यात क्षमता भी बढ़ानी है:मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत को कृषि उत्पादन में न केवल आत्म निर्भर बनना है बल्कि वैश्विक बाजार के लिए उत्पादन भी करना है। मोदी ने कहा, हमें आयात कम करना है और निर्यात बढ़ाना है। मोदी ने इस उद्देश्य की प्राप्ति में पीएम धन-धान्य कृषि योजना तथा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। वह नयी दिल्ली में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) में आयोजित विशेष कृषि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं और योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया।

इनमें 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ रुपये का 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन' दो प्रमुख कार्यक्रम हैं। पीएम धन धान्य योजना का उद्देश्य 100 जिलों में कृषि का कायाकल्प करना है। इसी तरह दलहन में आत्मनिर्भरता का मिशन दलहन खेती का रकबा बढ़ा कर और खरीद, प्रसंस्करण और वितरण जैसी मूल्य संवर्धन श्रृंखलाओं को मजबूत करके पूरा किया जाना है। कार्यक्रम को कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कृषि उत्पादन में आत्म निर्भरता और निर्यात बढ़ाने के इन लक्ष्यों की प्राप्ति में पीएम धन-धान्य कृषि योजना तथा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि



पीएम धन-धान्य योजना के लिए सौ जिलों का चयन तीन कसौटियों पर किया गया है। इसमें एक कसौटी खेती की पैदावार क्या है, दूसरी एक खेत में एक साल में खेती कितनी बार होती है तथा किसानों को कर्ज या निवेश की सुविधा कैसी है। उन्होंने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन सिर्फ दलहन उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का अभियान भी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़े इसके लिए पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन पर बल दिया जा रहा है। इससे छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों को ताकत मिली है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और महत्वपूर्ण हो रही है जहाँ गावों में नमो ड्रोन दीदिया खाद और कीटनाशक छिड़काव के आधुनिक तरीकों का नेतृत्व कर रही हैं। मोदी ने कहा, अपने किसान, पशुपालक और मछुआरा भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। इसी दिशा में आज दिल्ली से हजारों

करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास मेरे लिए गर्व का क्षण है। हमने किसानों के हित में...बीज से लेकर बाजार तक सुधार किए हैं।'

प्रधान मंत्री ने पूसा के इसी मंच से देश भर में जगह जगह कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र लोकार्पण किया। उन्होंने लगभग 815 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

आज शुरू की गयी परियोजनाओं में बेंगलुरु और जम्मू-कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र, अमरेली और बनास में उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत असम में आईवीएफ लैब की स्थापना शामिल है। इनके अलावा मेहसाणा, इंदौर और भीलवाड़ा में दूध पाउडर संयंत्र, तेजपुर (असम) में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली चारा संयंत्र के साथ-साथ कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढांचा, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना आदि शामिल हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश के कृष्णा में एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना (विकिरण), उत्तराखंड में ट्राउट मत्स्य पालन, नागालैंड में एकीकृत एक्का पार्क का सांकेतिक रूप से शिलान्यास भी किया। इनके अलावा कराईकल, पुदुचेरी में स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य पालन बंदरगाह और ओडिशा के हीराकुंड में अत्याधुनिक एकीकृत एक्कापार्क जैसी कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया।



मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 326 मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन की सौगात

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री बोले नारी शक्ति ही समाज की असली ताकत

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्यभर की 326 मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन प्रदान किए।

कार्यक्रम में जनपद स्तर पर हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं की प्रथम तीन टॉपर बालिकाओं तथा विकासखण्ड स्तर पर टॉपर बालिकाओं को भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सभी को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि इस वर्ष भी प्रदेश की बेटियों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से असाधारण सफलता अर्जित की है। उन्होंने बताया कि हाईस्कूल परीक्षा में कुल 90 प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे, जिनमें बालिकाओं की सफलता दर 93 प्रतिशत से अधिक रही। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में 83 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए, जिनमें बालिकाओं का सफलता प्रतिशत 86



प्रतिशत से अधिक रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि समाज की तरक्की नारी शक्ति से होती है। यदि किसी राज्य की महिलाएँ प्रगति कर रही हैं, तो उस राज्य के विकास को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि बेटियों के शिक्षित होने से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्ज्वल होता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण

दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना और नंदा गौरा योजना जैसी कई जनहितकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य की बेटियाँ सरकारी सेवाओं में चयनित होकर आत्मनिर्भर बन रही हैं तथा स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप और लघु उद्योगों के जरिये आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि



प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलें महिला सम्मान और सशक्तिकरण की मिसाल हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी महिला छात्रावास निर्माण, मुफ्त साइकिल योजना और

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की अनेक बेटियाँ सरकारी सेवा में जाने का सपना देख रही हैं, और उनके इस सपने को साकार करने के लिए राज्य में देश का सबसे कठोर नकल-विरोधी कानून लागू किया गया है। इसका परिणाम है कि पिछले चार वर्षों में 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है।

एक नजर

शान्तरशाह पुलिस चौकी प्रभारी ने लगायी जागरूकता चौपाल



पथ प्रवाह हरिद्वार। ड्रम्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए चौकी शान्तरशाह में हुई चौपाल में ग्रामीणों को नशा मुक्त शहर - नशा मुक्त गांव अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा आरंभ ड्रम्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 एवं जिंदगी को हां, नशे को ना अभियान की भावना के अनुरूप उपस्थित ग्रामीणों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर हरिद्वार पुलिस द्वारा ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया गया कि नशे के कारोबार या उसके सहयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नशा तस्करों की सहायता करता हुआ पाया गया, तो उसके विरुद्ध भी उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी जैसी नशा तस्करों के विरुद्ध की जाती है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, स्टोन क्रेशर संचालक के खिलाफ मुकदमा



पथ प्रवाह हरिद्वार। सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने वालों के विरुद्ध जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सख्ती से कार्यवाही कर रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विभिन्न माध्यम से प्राप्त सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला खान अधिकारी काजिम रजा को विभागीय दल के साथ छापेमारी के निर्देश दिए। जिला खान अधिकारी काजिम रजा के नेतृत्व में टीम द्वारा ग्राम बाड़ीटीप स्थित स्टोन क्रेशरों पर अचानक छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पाया गया कि मैसर्स अविनि स्टोन क्रेशर को 6 अक्टूबर को सीज किया गया था। इस स्टोन क्रेशर अर्थात् अविनि स्टोन क्रेशर के संचालक द्वारा सील को तोड़कर क्रेशर संचालित किया जाने व अवैध खनिज को लिए जाने के कारण क्रेशर के संचालक एवम् मालिक के विरुद्ध कोतवाली लक्सर के एफआईआर दर्ज कराते हुए क्रेशर को पुनः सील किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन एवम् भंडारण के विरुद्ध चल रही कार्यवाही जारी रहेगी और सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रदद की यूकेएसएसएससी परीक्षा, तीन माह में दोबारा परीक्षा

सरकार ने परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने में प्रतिबद्धता जताई, सीबीआई जांच की संस्तुति भी की गई

पथ प्रवाह, देहरादून

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 21 सितंबर 2025 को आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के चंद घंटों बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परीक्षा को निरस्त कर दिया और तीन माह में दोबारा परीक्षा कराने का आश्वासन दे दिया।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी की जांच रिपोर्ट के बाद सरकार ने त्वरित निर्णय कर छात्रों का भरोसा जीतने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि आयोग ने अल्प समय में अधिक से अधिक जनसुनवाई कर अभ्यर्थियों एवं संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त किए और रिपोर्ट तैयार की, जो अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट का परीक्षण कर अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि मामले की पूरी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने सीबीआई जांच की संस्तुति भी की है। उन्होंने स्पष्ट किया



कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की कोई संभावना न रहे और अभ्यर्थियों तथा उनके अभिभावकों का राज्य की परीक्षा प्रणाली पर विश्वास लगातार बना

रहे। इस अवसर पर आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया में पाए गए प्रारंभिक निष्कर्ष और सुझाव मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से अंतरिम रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर विचार किया गया। जिसके बाद परीक्षा को निरस्त करने का आदेश शासन ने जारी कर दिया।

घर से लाखों के जेवर और नकदी चोरी कर फरार हुई नौकरी गिरफ्तार

पथ प्रवाह संवाददाता।

हरिद्वार। मां की बीमारी के लिए घर में रखे लाखों के जेवर और नकदी चोरी कर फरार हुई नौकरानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नौकरानी के पास से पुलिस ने चोरी किया सामान भी बरामद कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक मनीष चौहान निवासी मोहल्ला चौहानान, कोतवाली ज्वालापुर, हरिद्वार ने पुलिस को तहरीर देकर घर में कार्यरत नौकरानी शशि देवी उर्फ छोटी द्वारा बीती अक्टूबर को घर में रखी नगदी करीब 8 लाख 30 हजार रुपये और 4 जोड़ी बिछुए, 1 जोड़ी पाजेब, 1 अंगूठी (सोने की) चोरी कर लिए जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया। टीमों द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। स्थानीय लोगों से गहन पूछताछ की गई। जांच के दौरान पीड़ित के घर में कार्यरत नौकरानी जो जगजीतपुर में राजा गार्डन कालोनी के पास रहती थी, उसकी गतिविधि संदिग्ध पायी गई। पुलिस टीम द्वारा नौकरानी के कमरे पर दबिश दी गई। वहां नौकरानी से पूछताछ करने पर



उसने चोरी किये जाने की बात स्वीकार कर ली। बताया कि उसने मनीष के पिता को अलमारी में पैसा रखते देखा था और उसी अवसर का लाभ उठाकर चोरी की। कमरे की तलाशी लेने पर 2,77,000/- नगद बरामद हुए। शेष राशि के बारे में पूछताछ करने पर

नौकरानी ने बताया कि बाकी रकम उसने घर के बाहर गली में रेत के नीचे छिपा रखी है। उनकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने वहां से 3,47,000/- नगद, 4 जोड़ी बिछुए (सफेद धातु), 1 जोड़ी पाजेब (सफेद धातु) एवं 1 अंगूठी (पीली धातु) बरामद की।



पंतजलि गुरुकुलम् भारत की कालजयी, मृत्युंजयी संस्कृति, आर्ष परंपरा और वैदिक संवेदनाओं के संरक्षण-संवर्धन की अद्भुत प्रयोगशाला: जूनापीठाधीश्वर

पथ प्रवाह संवाददाता।

हरिद्वार। भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत संचालित पंतजलि गुरुकुलम् का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पंतजलि योगपीठ के परामाध्यक्ष स्वामी रामदेव ने कहा कि हमारे प्राचीन गुरुकुलों की गुरु-शिष्य परंपरा में ज्ञान के साथ-साथ नैतिकता, चरित्र की शुद्धता, वाणी-व्यवहार में मृदुता तथा आचरण सिखाया जाता था। प्राचीन गुरुकुलों से शिक्षित होकर विद्यार्थी विश्व का नेतृत्व करते थे। पंतजलि गुरुकुलम् भी प्राचीन ऋषि परंपरा का अनुसरण कर विद्यार्थियों को विश्व नेतृत्व के लिए तैयार कर रहा है।

स्वामी रामदेव ने बताया कि पंतजलि गुरुकुलम् में तीन से पाँच साल के बच्चों से लेकर 12वीं कक्षा तक देश के लगभग सभी प्रांतों के बच्चे अध्ययनरत हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद, भगवान वसुन्ना, संत मणिबाड़ेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत रविदास, संत कबीरदास आदि सभी पूर्वज ऋषि-ऋषिकाओं ने समाज में व्याप्त कुुरीतियों, बंधनों, भेदभाव की सारी दीवारों को तोड़कर एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य का संदेश दिया।

उन्होंने हमें बताया कि सम्पूर्ण सृष्टि में एक



ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा का सर्वत्र वास है। इन तत्वों व दिव्य संदेशों तथा सनातन के शाश्वत सत्यों को पूरी मानवता के लिए पूर्ण प्रामाणिकता के साथ समाज में संप्रेषित किया। हमें बताया कि वेद में कोई भेद नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि पंतजलि गुरुकुलम् के आचार्यगण विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं जिससे उनका

जीवन का उत्कर्ष प्राप्त कर रहा है।

कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज ने कहा कि पंतजलि गुरुकुलम् भारत की कालजयी, मृत्युंजयी संस्कृति, आर्ष परंपरा और वैदिक संवेदनाओं के संरक्षण-संवर्धन की अद्भुत प्रयोगशाला है। पंतजलि गुरुकुलम् के विद्यार्थियों में मानवीय चेतना का उन्नत स्वरूप

जागृत हो रहा है। पंतजलि गुरुकुलम् का यह दीप स्वामी रामदेव जी ने प्रकाशित किया है जो पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा।

आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा कि पंतजलि गुरुकुलम् से भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं व मान्यताओं को बल मिला है। पंतजलि में बच्चे न केवल ज्ञानार्जन कर रहे हैं अपितु संस्कारित भी हो रहे हैं। उनके अभिभावकों ने जिन संस्कारों के लिए अपने बच्चों को पंतजलि भेजा है, वे भी आज गौरवान्वित अनुभव कर रहे होंगे। उनके स्वप्न उनके बच्चे पंतजलि के माध्यम से साकार कर रहे हैं। परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि ने कहा कि पंतजलि गुरुकुलम् के बच्चों को देखकर जो मैंने अनुभव किया, भावी पीढ़ियों में इन्हीं शाश्वत सत्यों को उद्घाटित करने की आवश्यकता है। देश का दुर्भाग्य है कि जो छपना चाहिए था वह छिपाया गया और जो था ही नहीं वह दिखाया जाता रहा। देश के वास्तविक इतिहास के मूल में सनातन ही है। आज का समय भारत को भारत की आँखों से देखने का है और पंतजलि गुरुकुलम् इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। महामण्डलेश्वर हरिचेतना नंद जी महाराज ने कहा कि इस

धराधाम पर अधुनातन काल से संतों की जो लब्ध प्रतिष्ठित श्रृंखला चली आ रही है, स्वामी रामदेव जी महाराज उस श्रृंखला की अहम कड़ी हैं। पंतजलि गुरुकुलम् से स्वामी रामदेव जी ने सनातन का संदेश पूरी दुनिया को दिया है।

कार्यक्रम में शैक्षणिक, क्रीड़ा तथा शास्त्र प्रतियोगिताओं में पंतजलि गुरुकुलम् के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में पंतजलि गुरुकुल ज्वालापुर, पंतजलि कन्या गुरुकुलम् देवप्रयाग, पंतजलि गुरुकुलम् हरिद्वार के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य तथा नाट्य प्रस्तुतियाँ दीं जिससे उपस्थित अतिथिगण अभिभूत थे।

पंतजलि गुरुकुलम् के अष्टम वार्षिकोत्सव में साध्वी भगवती जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. एन.पी. सिंह आदि ने आशीर्वाद उद्घोषण से विद्यार्थियों को अभिषिक्त किया। इस अवसर पर माता गुलाब देवी, डॉ. यशवंत शास्त्री, साध्वी आचार्य देवप्रिया, डॉ. ऋतंभरा शास्त्री, बहन अंशुल शर्मा, बहन पारूल शर्मा, साध्वी देवमयी, साध्वी देवसुधा, साध्वी देवाराधना, साध्वी देवश्रुति, साध्वी देवाश्रिता, साध्वी देवांजला, साध्वी देवशक्ति, स्वामी ईशदेव, स्वामी विरक्तदेव आदि उपस्थित रहे।

एक नजर

रुड़की में सख्ती से चला नो हेलमेट—नो फ्यूल अभियान



पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। जिलाधिकारी और एसएसपी के निर्देश रुड़की में पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के पर्यवेक्षण में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरूआत की गई। इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों से कहा गया कि यदि वह बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने आएंगे तो उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस अभियान की शुरूआत एसपी देहात और एआरटीओ ने हरी झंडी दिखाकर की। परिवहन विभाग व यातायात पुलिस विभाग रुड़की द्वारा संयुक्त रूप से हेलमेट के प्रति जागरूकता हेतु नो हेलमेट, नो फ्यूल अभियान प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ एसपी देहात शेखर चंद सुयाल, एआरटीओ कृष्ण पलड़िया व टीआई सदीप सिंह नेगी द्वारा शिखा पेट्रोल पंप गणेशपुर से किया गया। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक यातायात हरिद्वार द्वारा बताया गया कि इस प्रकार का अभियान निरंतर रुड़की व हरिद्वार शहर में आयोजित किए जाएंगे। परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि दो-पहिया वाहन चालक हेलमेट पहने के बाद ही ईंधन प्राप्त कर सकेंगे। हेलमेट न पहनने पर पेट्रोल/डीजल/सीएनजी सेवा नहीं दी जायेगी। यह कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने, सिर-मस्तिष्क की चोटों को रोकने और सुरक्षित राइडिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है।

सीपीयू ने दो दिन में किये 60 ई रिक्शा चालकों के चालान



पथ प्रवाह हरिद्वार। त्योहारी सीजन के दृष्टिगत आमजन की सुरक्षा तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से यातायात पुलिस रुड़की एवं सीपीयू टीम रुड़की द्वारा संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शुक्रवार व शनिवार को रुड़की शहर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाकर बिना दस्तावेजों के एवं यातायात नियमों के विरुद्ध संचालित 60 ई-रिक्शा चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई तथा 17 ई-रिक्शा सीज किए गए। त्योहारों के दौरान सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा नियम उल्लंघन करने वालों पर सतत सख्त कार्यवाही की जा रही है। हरिद्वार पुलिस ने अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें, वाहन के समस्त आवश्यक दस्तावेज साथ रखें तथा सड़क सुरक्षा में सहयोग करें।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में एनसीसी कैडेट्स ने सीखे बाढ़ से बचाव के टिप्स

पथ प्रवाह संवाददाता।

हरिद्वार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित युवा आपदा मित्र परियोजना के अंतर्गत गुरुकुल कांगड़ी में एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में दूसरे दिन कैडेट्स को बाढ़ से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। बाढ़ के दौरान किस प्रकार राहत और बचाव कार्य संचालित किए जा सकते हैं, इसके तकनीकी पहलुओं से रूबरू कराया गया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में आयोजित शिविर के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर दीपक द्वारा कैडेट्स को बाढ़ से संबंधित खतरों, उनसे बचाव के तरीकों, और आपात स्थिति में किए जाने वाले प्राथमिक उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने आकस्मिक स्थिति में स्थानीय संसाधनों जैसे प्लास्टिक की बोतलें, बांस, रस्सी आदि की मदद से तैरने वाले उपकरण (इम्प्रोवाइज्ड फ्लोटेशन डिवाइसेज) बनाने का तरीका बताया, जिससे सीमित संसाधनों में भी लोगों की जान बचाई जा सकती है। एनडीआरएफ टीम द्वारा इन उपकरणों का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया, जिससे कैडेट्स को रेस्क्यू तकनीकों को प्रत्यक्ष रूप से देखने और सीखने का अवसर मिला।

राफ्ट और लाइफ जैकेट बनानी सीखी

इस दौरान कैडेट्स ने केरोसिन टिन राफ्ट, चारपाई राफ्ट, बांस से बनी राफ्ट, बैरल राफ्ट, केले के वृक्ष से बनी राफ्ट, ट्यूब राफ्ट, पानी की बोतल से बनी राफ्ट व लाइफ जैकेट, थर्मोकोल से बनी लाइफ जैकेट बनाने की विधि को सीखा। इसके साथ ही पानी में डूब रहे व्यक्ति को किस प्रकार बचाया जा सकता है, इसके बारे में भी कैडेट्स को बताया गया। कैडेट्स ने रीच विधि, थ्रो विधि, वेड विधि, वेट रेस्क्यू,



काटेक्ट टो रेस्क्यू आदि तकनीक को भी सीखा।

मूल अवधारणाओं से अवगत कराया

प्रशिक्षण के पहले सत्र में मास्टर ट्रेनर मनोज कंडियाल द्वारा कैडेट्स को आपदा प्रबंधन की मूल अवधारणाओं से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि आपदा केवल एक घटना नहीं होती, बल्कि इसके सामाजिक, आर्थिक व मानसिक प्रभाव होते हैं। इस दौरान आपदाओं के प्रकार, उनकी गंभीरता, युवाओं की भूमिका और आपदा की स्थिति में किए जाने वाले त्वरित उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। बता दें कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सजग, सक्षम और उत्तरदायी नागरिक के रूप में तैयार करना है, ताकि वे आपदा की स्थिति में स्वयं की और दूसरों की रक्षा कर सकें तथा अपने समुदाय में जन-जागरूकता फैलाकर आपदा जोखिम को कम करने में योगदान दे सकें।

साइबर सेल ने गुरुकुल कांगड़ी में चलाया जागरूकता अभियान

पथ प्रवाह संवाददाता

हरिद्वार। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पूरे जनपद में सभी थानाध्यक्ष और थाना प्रभारी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को साइबर क्राइम सेल हरिद्वार द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में 31 यूके बटालियन एनसीसी हरिद्वार के करीब 300 अधिकारीगण एवं कैडेट्स सम्मिलित हुए। टीम द्वारा प्रतिभागियों को वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रकारों, उनके नए तरीकों तथा साइबर ठगी से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थित सभी कैडेट्स को जागरूकता संबंधी पंपलेट्स वितरित किए गए। किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय हेलपलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया।



कहा कि साइबर अपराधों से सतर्क रहें, अजनबियों द्वारा भेजे गए लिंक या कॉल पर

व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है।



मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने की राज्य की पहली केन्द्रीयकृत वर्चुअल एवं स्मार्ट कक्षा स्टूडियो की शुरुआत

840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित होंगी कक्षाएं, डिजिटल शिक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम

पथ प्रवाह, ब्यूरो प्रमुख, योगेश शर्मा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननुरखेड़ा (देहरादून) में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी योजना के अंतर्गत संचालित वर्चुअल एवं स्मार्ट कक्षाओं के केन्द्रीयकृत स्टूडियो का शुभारंभ किया। इस स्टूडियो के माध्यम से अब प्रदेश के 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में शिक्षा संचालित होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की यह एक ऐतिहासिक पहल है, जिससे प्रदेश के विद्यार्थियों का भविष्य और अधिक उज्ज्वल होगा। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि डिजिटल तकनीक, वर्चुअल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा अधिक प्रभावी, आकर्षक और सहज बन गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि प्रदेश में 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है, वहीं 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं पहले से संचालित हैं। उन्होंने कहा कि अब विद्यार्थी 'उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग एप्लीकेशन' के



माध्यम से घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप से विद्यार्थी स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकेंगे और राज्य के साथ-साथ देश के नामी शिक्षकों से सीधे संवाद का अवसर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार 5-पीएम ई-विद्या चैनल के माध्यम से भी दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य में कक्षा 6 से 12 तक के मेधावी छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी

छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। साथ ही, प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजा जा रहा है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 8 ट्रेडों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है, जिससे अब तक 42 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का चयन

प्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ है। इस पहल की सराहना केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहाँ बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की गई है। विद्यालयों में 'बस्तारहित दिवस' (Bagless Day) को शामिल किया गया है। स्थानीय भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी भाषाओं में पुस्तकें तैयार की गई

हैं, वहीं थारू, बोक्सा और रवांटी भाषाओं में शब्दकोश निर्माण का कार्य भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि 'हमारी विरासत' पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, परंपरा और महान विभूतियों से परिचित कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। इसी नीति के अनुरूप राज्य में आईसीटी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण संसाधन और वर्चुअल कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सर्वप्रथम लागू किया। इसके तहत वर्ष 2022 में 'बाल वाटिका' की शुरुआत की गई। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें अनिवार्य की गई हैं तथा कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा 'काऊ', अपर सचिव शिक्षा श्रीमती रंजना राजगुरु, महानिदेशक शिक्षा दीपि सिंह, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से राज्यभर के विद्यालयों के विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित रहे।

एक नजर

सड़क निर्माण में घटिया सामग्री की शिकायत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी निलंबित

पथ प्रवाह, हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से अमल में ला रहा है। इसी क्रम में भ्रष्टाचार के आरोप में जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह द्वारा एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को निलंबित किया गया है। जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि ग्राम पंचायत अकौड़ा खुर्द विकास खण्ड लक्सर के कश्यप बस्ती में सीसी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री की शिकायत पर सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार को प्रकरण में जाँच के निर्देश दिए गए थे। इस काम में सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2025 को ग्राम पंचायत अकौड़ा खुर्द में मौके पर जा कर शिकायत में उल्लेखित सड़क की जाँच की गयी। सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार ने अपनी जाँच आख्या दिनांक 21 अगस्त, 2025 कार्यालय में प्रस्तुत की गयी, जिसमें बताया गया कि शिकायत में उल्लेखित सड़क ग्राम पंचायत अकौड़ा खुर्द द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि से निर्मित की गयी है। शिकायत में उल्लेखित सड़क जयपाल के घर से प्रदीप के घर की ओर सीसी सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत अकौड़ा खुर्द द्वारा कराया गया था। जांच के दौरान सड़क की गुणवत्ता खराब पायी गयी, सड़क के किनारे नाली का निर्माण बिना लेवल के औचित्यहीन रूप से मिला। समित कुमार निवासी अकौड़ा खुर्द ने शिकायत में बताया कि खराब गुणवत्ता की सड़क पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी शंकरदीप एवं कनिष्ठ अभियन्ता (पं) (आऊटसोर्स) मनोज कुमार द्वारा लीपा-पोती के उद्देश्य से सड़क के ऊपर नयी सीसी मार्ग डाल दी गयी है। जांच में यह शिकायत भी सही पायी गई। इस गम्भीर अनियमितता के दृष्टिगत शंकरदीप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अकौड़ा खुर्द को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

नाबालिग का शारीरिक शोषण करने वाले दोषी को 10 साल की सजा

पथ प्रवाह, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ पुलिस ने पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़ गोविन्द बल्लभ जोशी और क्षेत्राधिकारी धारचूला केएस रावत के पर्यवेक्षण में एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। न्यायालय ने नाबालिग से शारीरिक शोषण के मामले में अभियुक्त को कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। वर्ष 2024 में कोतवाली धारचूला क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एक व्यक्तिय द्वारा उनकी पुत्री का शारीरिक शोषण किया है। इस तहरीर के आधार पर कोतवाली धारचूला में अभियुक्त राजू पुत्र मुन्नी लाल निवासी ग्राम सदीला, हरदोई उत्तर प्रदेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मेघा शर्मा द्वारा की गई, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट जांच प्रक्रिया के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मामले की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजन पोक्सो प्रेम सिंह भण्डारी ने की। सुनवाई के बाद न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने अभियुक्त राजू उपरोक्त को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष का कारावास एवं 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। यदि वह अर्थदंड का भुगतान नहीं करेगा, तो उसे पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सौगात, वनकर्मियों को दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती पर आवासीय भत्ता

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के वन कर्मियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि वन विभाग के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कर्मियों को अब आवासीय भत्ता प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे वनकर्मियों प्रदेश की बहुमूल्य वन संपदा और वन्यजीवों की रक्षा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निरंतर कार्यरत रहते हैं। वे दूरस्थ और दुर्गम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने परिवारों से दूर रहते हैं, जिससे उन्हें आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने उनकी इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि जहां



स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां तैनात वन कर्मियों को आवासीय भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह निर्णय उन वनकर्मियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा जो जंगलों की सुरक्षा और

वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शासन स्तर पर वित्त विभाग की सहमति से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां यह सुविधा लागू होगी। वन विभाग के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि सरकार के इस निर्णय से उन्हें अपने परिवारों की देखभाल करने में सहायता मिलेगी और वे राज्य की वन संपदा की सुरक्षा में और अधिक समर्पण के साथ कार्य कर सकेंगे। इस निर्णय को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सरकार के कर्मचारी हितैषी रुख का एक और उदाहरण माना जा रहा है, जो प्रदेश के कर्मियों की कार्य परिस्थितियों और जीवन स्तर में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद सुनील सैनी ने की मुख्यमंत्री से भेंट

पथ प्रवाह देहरादून।

पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष सुनील सैनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान पिछड़ा वर्ग समाज के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मिले इसके लिए हम संकल्पित हैं।

सुनील सैनी ने बताया सरकार पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरियों, और आर्थिक विकास पर केंद्रित विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिनमें छात्रवृत्ति, छात्रावास, कौशल विकास और ऋण सुविधाएं शामिल हैं। ये कदम आरक्षण के माध्यम से सामाजिक समानता सुनिश्चित करने और उनके समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे हैं। कहा कि धामी सरकार में अहम कानून लागू हुए हैं, जिनमें समान नागरिक संहिता (श्रृष्ट),



नया भू-कानून, नकल विरोधी कानून यह ऐतिहासिक है उत्तराखंड राज्य निरंतर विकास की और गतिमान है। अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेटियों के

शिक्षित होने से भावी पीढ़ियों का भविष्य भी संवरता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में नारी शक्ति को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।



कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत किसानों को मिलेगा समेकित योजनाओं का लाभ, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

आकांक्षी जिलों के किसानों को मिलेगा नई योजनाओं का लाभ, उत्तराखंड के अल्मोड़ा व चमोली जिले भी शामिल

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद, पूसा (नई दिल्ली) में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 'पीएम धन-धान्य कृषि योजना' और 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी देशभर की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया।

इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उत्तरकाशी जिले में भी किया गया, जिसमें जिलेभर के किसानों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। शनिवार को जिला प्रेक्षागृह में कृषि विभाग के तत्वावधान में सीधा प्रसारण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर जिला



पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान एवं जिलाधिकारी प्रशांत आर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिले के 100 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने भाग लेकर नई कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम के दौरान कृषि, उद्यान, मत्स्य, रिप, पशुपालन विभागों द्वारा विभागीय स्टॉल स्थापित किए गए, जिनमें किसानों को

आधुनिक कृषि उपकरणों, नवीन तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष और जिलाधिकारी ने किसानों को कृषि यंत्र भी वितरित किए।

जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन किसानों के लिए

परिवर्तनकारी पहल है। उन्होंने कहा कि यह योजनाएं न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक होंगी, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त करने हेतु अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा आज जिन योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, वे देश के आकांक्षी जिलों में लागू होंगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और चमोली जिले भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह योजनाएं भारत सरकार की 36 अन्य कृषि योजनाओं के साथ समेकित रूप में लागू की जाएंगी ताकि किसानों को एक ही

प्लेटफॉर्म पर सभी योजनाओं का समग्र लाभ मिल सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि विभाग आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी भूमि की प्रकृति, जलवायु और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फसलों का चयन करें, जिससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि हो सके। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, फसल विविधिकरण, जैविक खेती और समूह आधारित खेती अपनाने के लिए भी प्रेरित किया।

इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी एस.एस. वर्मा, सीएचओ डॉ. रजनीश सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

एक नजर

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा पिथौरागढ़



जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 35,440 करोड़ रुपये की कृषि योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम से जनपद पिथौरागढ़ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा। प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में आयोजित विशेष कृषि कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान किसानों से संवाद किया और जनसभा को भी संबोधित किया। विकास भवन सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के किसान, दर्जा राज्यमंत्री गणेश भंडारी, नगर निगम पिथौरागढ़ की मेयर कल्पना देवलाल, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास आशीष पुनेठा, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी, मुख्य उद्यान अधिकारी अभिनव टम्टा सहित कृषि, बागवानी एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। विकास भवन के साथ साथ समस्त विकास खण्ड मुख्यालय पर, केवीके गैना तथा सहकारिता विभाग की समस्त समितियों में भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश के प्रमाणित किसानों, ऋद्धिब्रह्म तकनीशियनों एवं परिवर्तित ऋद्धि प्रतिनिधियों को प्रमाणपत्र वितरित किए तथा दाल उत्पादक किसानों से संवाद भी किया। जनपद के किसानों, अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने विकास भवन एवं अन्य केंद्रों में प्रधानमंत्री के लाइव संबोधन को बड़े उत्साह के साथ सुना।

आग से बचाव की दी गई जानकारी



पथ प्रवाह पिथौरागढ़। पुलिस महानिरीक्षक अग्निशमन एवं आपात सेवा व पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ निर्देशन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी नरेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में आग से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया गया। थाना नाचनी और पीएम राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी में फायर सर्विस द्वारा पुलिसकर्मियों को एवं विद्यालय के स्टाफ को अग्निशमन उपकरणों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और अन्य स्कूल कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं तथा उपकरणों के प्रयोग की विधियों का डेमो भी प्रस्तुत किया गया।

गंगोत्री से लौट रही महिला श्रद्धालु का पर्स 35 हजार नकदी सहित मनेरी पुलिस ने लौटाया

ईमानदारी और तत्परता का परिचय देते हुए पुलिस टीम ने रेस्टोरेंट से खोजकर वापस किया खोया सामान

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। चारधाम यात्रा पर बीड़ (महाराष्ट्र) से आई महिला श्रद्धालु मेघा रमाकांत धर्माधिकारी का पर्स 35 हजार रुपये नकदी और जरूरी कागजात सहित मनेरी पुलिस टीम ने बरामद कर उन्हें लौटा दिया।

जानकारी के अनुसार मेघा रमाकांत धर्माधिकारी 10 अक्टूबर को गंगोत्री धाम दर्शन के उपरांत वापसी के दौरान डबरानी पुल के पास एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए रुकी थीं। उसी दौरान उनका पर्स रेस्टोरेंट में ही छूट गया, जिसमें 35 हजार रुपये नकद, आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। पर्स गुम होने की सूचना मिलते ही मनेरी कोतवाली पुलिस टीम सक्रिय हुई और तत्काल जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस ने आसपास के रेस्टोरेंट संचालकों से संपर्क किया, जिसके बाद रेस्टोरेंट मालिक के पास



से वह पर्स सुरक्षित बरामद किया गया।

आज शनिवार को मनेरी कोतवाली परिसर में पुलिस टीम ने पर्स को नकदी और कागजात सहित महिला श्रद्धालु को सौंप दिया। पर्स वापस मिलने पर मेघा रमाकांत धर्माधिकारी ने उत्तरकाशी पुलिस का आभार व्यक्त किया और कहा कि पुलिस की

ईमानदारी और संवेदनशीलता से उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। स्थानीय लोगों ने भी मनेरी पुलिस की तत्परता और सजगता की सराहना की, इसे चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहयोग के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

शिक्षा, अधिकार और नेतृत्व से ही सशक्त होगी हर बालिका बड़कोट में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

बड़कोट/उत्तरकाशी। माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार एवं मा0 जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी गुरुबख्खा सिंह के मार्गदर्शन में राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज, बड़कोट उत्तरकाशी में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक विशेष विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं, अध्यापकों एवं जनसामान्य को बालिकाओं के शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी अधिकारों से संबंधित जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि बालिकाओं को समान अवसर और सुरक्षा देना समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक शिक्षित व सशक्त बालिका ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला रखती है। जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बालिका



दिवस की शुरुआत 1995 के बीजिंग महिला सम्मेलन से हुई थी, जिसमें विश्वभर की महिलाओं ने लड़कियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। इसके उपरांत, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 में 11 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता दी। इस वर्ष की थीम लड़कियों का नेतृत्व और उनकी स्वतंत्र पहचान रखी गई है, जो यह संदेश देती है कि लड़कियां केवल भविष्य की आशा नहीं,

बल्कि वर्तमान में परिवर्तन लाने की असली शक्ति हैं। प्रत्येक बालिका में समाज को दिशा देने की क्षमता होती है, आवश्यकता केवल उसे पहचानने और अवसर प्रदान करने की है।

शिविर में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग सहित विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएँ, छात्राएँ एवं अन्य कर्मचारीगणों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

अंतराष्ट्रीय बालिका दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित बेटियों के अधिकार, शिक्षा और सशक्तिकरण पर हुआ संवाद

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार एवं मा0 जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी गुरुबख्खा सिंह के मार्गदर्शन में आज 'अंतराष्ट्रीय बालिका दिवस' के अवसर पर

एक विशेष विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ज्ञान ज्योति स्कूल, धिवारा उपला, पुरोला में प्रातः 8:00 बजे से 10:00 बजे तक आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता विवेक शर्मा, अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति, पुरोला, उत्तरकाशी ने की। शिविर के दौरान छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों को

बालिकाओं की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, तथा उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

वक्ताओं ने बताया कि बालिकाओं के सशक्तिकरण से ही समाज में वास्तविक प्रगति संभव है और प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करे।

लोक सेवा आयोग की लापरवाही उजागर - अभ्यर्थी के मूल अभिलेख गायब, सूचना आयोग ने जांच व क्षतिपूर्ति के आदेश दिए

सुरेंद्र पाल सिंह

देहरादून। उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून में डा0 शम्भू प्रसाद नौटियाल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार प्रकरण की सुनवाई के दौरान एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में यह तथ्य उजागर हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को पंजीकृत डाक से भेजे गए मूल अभिलेख आयोग के कार्यालय में पंजीकरण के बाद भी उपलब्ध नहीं हैं।

सूचना आयोग ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के सचिव को निर्देशित किया है कि वे अभ्यर्थी के दस्तावेजों के न मिलने, खो जाने या विनाश किए जाने की स्थिति की निशानुसार जांच कराएं और अगली सुनवाई से पूर्व विस्तृत आख्या आयोग को भेजें।

मामला कैसे शुरू हुआ

अपीलाधी डा0 शम्भू प्रसाद नौटियाल, ग्राम भाटगांव, पोस्ट थाती, धनारी, जिला उत्तरकाशी निवासी हैं। उन्होंने सूचना का



अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 19 मार्च 2025 को दो बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। पहले बिंदु पर उन्हें संतोषजनक सूचना

प्राप्त हुई, किंतु दूसरे बिंदु पर – जिसमें उन्होंने अपने द्वारा 28 मई 2022 को भेजे गए पंजीकृत पत्र (Consignment No. RV773146306IN) के अंतर्गत भेजे गए अभिलेखों की प्रमाणित प्रति मांगी थी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

लोक सूचना अधिकारी ने बताया कि पत्र की प्राप्ति पंजिका में दर्ज है, लेकिन संबंधित अभिलेख सेवा अनुभाग-2 की पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं।

असिस्टेंट प्रोफेसर चयन से जुड़ा मामला

डा0 नौटियाल ने असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के अंतर्गत आवेदन किया था। आयोग के अनुसार, उन्होंने अपने आवेदन के साथ विज्ञापन में मांगा गया परिशिष्ट-3 प्रमाण पत्र (क्व्.ष्ठ. हेतु) प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण उन्हें 01 नवम्बर 2023 की अनर्हता सूची में शामिल कर दिया गया और बाद में 15 फरवरी 2024 को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया।

डा0 नौटियाल ने इस निर्णय को उच्च न्यायालय नैनीताल में चुनौती दी, जहाँ से

आयोग ने जताई गंभीर चिंता

मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी ने अपने आदेश में कहा कि यह अत्यंत गंभीर प्रकरण है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा भेजे गए दस्तावेज पंजीकृत होने के बाद भी कार्यालय से लापता हो जाएं। यह न केवल पारदर्शिता की भावना के विपरीत है, बल्कि सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।

क्षतिपूर्ति पर कारण बताओ नोटिस

सुनवाई के दौरान डा0 नौटियाल ने आयोग को एक पत्र (दिनांक 25 सितंबर 2025) प्रस्तुत कर मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए ₹5,000 की क्षतिपूर्ति की मांग की। इस पर सूचना आयोग ने लोक प्राधिकारी / सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को धारा 19(8)(ख) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न अभ्यर्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में यह राशि प्रदान की जाए।

अगली सुनवाई 19 नवम्बर को

आयोग ने पूरे प्रकरण की अग्रेतर सुनवाई 19 नवम्बर 2025 को निर्धारित की है और तब तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला न केवल सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है, बल्कि सरकारी विभागों में दस्तावेजों की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही की गंभीर स्थिति को भी उजागर करता है।

उनकी रिट याचिका 18 मार्च 2025 को खारिज कर दी गई। वर्तमान में उनका प्रकरण उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है।

जेपी जयंती पर जगह-जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम, राधाकृष्णन ने किया लोकनायक के गांव का दौरा

नयी दिल्ली। स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के विरुद्ध सम्पूर्ण क्रांति का नारा देकर 1970 के दशक में युवाओं का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 123वीं जयंती पर शनिवार को उनको मानने वालों ने जगह-जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किये।

दिवंगत नेता को सोशल मीडिया पर भी याद किया और इसमें गणमान्य से लेकर सामान्य जन तक ने जयप्रकाश नारायण के देश की राजनीति में महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के महती योगदान का उल्लेख किया।

जेपी नाम से लोकप्रिय जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस बार एक बड़ा कार्यक्रम बिहार के सारण जिले में उनकी जन्मस्थली सीताब दियारा गांव में उनके पैतृक घर पर हुआ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार को सीताब दियारा पहुंच कर महान नेता की स्मृतियों को याद किया और वहां घर में रखे उनके अभिलेखों और स्मृति चिह्नों को देखा।

उपराष्ट्रपति ने उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायणजी की 123वीं जयंती पर बिहार के सारण जिले में उनके पैतृक गांव सीताब दियारा में उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने बाद में लाला टोला, सिताब दियारा स्थित जयप्रभा स्मृति भवन में प्रदर्शनी गैलरी का अवलोकन किया जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी की स्मृति में स्थापित किया गया है। राधाकृष्ण ने इस बात का भी उल्लेख किया कि किस प्रकार वह व्यवस्था परिवर्तन के जेपी के आह्वान पर 19 वर्ष की आयु में संपूर्णक्रांति के आंदोलन में जुड़ गये



थे। जेपी आंदोलन के बाद केंद्र में पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सामाजिक-राजनीतिक जागृति को प्रेरित करने में जेपी की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने आपातकाल के दौरान लिखी गई लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जेल डायरी के 25 जुलाई, 1975 को लिखे दुर्लभ पृष्ठ को भी साझा किया।

श्री मोदी ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने विशेष रूप से बिहार और गुजरात में कई जन आंदोलनों को प्रेरित किया, जिससे पूरे भारत में सामाजिक-राजनीतिक जागृति आई। इन आंदोलनों ने केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को हिलाकर रख दिया, जिसने आपातकाल लागू किया और संविधान को रौंद डाला।

उन्होंने कहा कि जेपी ने अपना जीवन आम नागरिकों को सशक्त बनाने और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया। उनके संपूर्ण क्रांति के आह्वान ने एक

वैष्णव ने नयी दिल्ली स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारियों का लिया जायजा

नयी दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर की गयी तैयारियों का जायजा लेने शनिवार को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और अधिकारियों से बात कर स्थिति का आकलन किया।

श्री वैष्णव ने स्टेशन पर होल्डिंग परिया का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से कहा, + नयी दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की अचानक भीड़ उमड़ पड़ती है। इसे देखते हुए दो साल पहले एक अस्थायी होल्डिंग परिया के साथ एक प्रयोग किया गया था। उस प्रयोग से यहां आने वाले यात्रियों को बहुत लाभ हुआ। अब,



एक स्थायी क्षेत्र और यात्री सुविधा केंद्र, बनाया गया है। इससे आने वाले यात्रियों, खासकर बिना आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को सुविधा

होगी। उन्होंने बताया कि अंदर के सभी टिकट काउंटरों को स्थानांतरित किया जा रहा है... यात्रियों के आने पर उन्हें स्वागत योग्य वातावरण, बैठने के लिए एक बड़ा क्षेत्र और बड़ी संख्या में शौचालय मिलेंगे। यह नयी दिल्ली स्टेशन के लिए एक स्थायी सुविधा है। देश भर के 76 स्टेशनों पर इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि यात्रियों को प्लेटफार्मों पर भीड़ न लगानी पड़े। इस व्यवस्था को एक नये स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, छठ और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान अचानक भीड़ बढ़ जाती है।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्प्लैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालय: 41, शांतिपुरम, जगजीपूर, कनखल, हरिद्वार पिन-249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, सुरेन्द्र पाल सिंह (ब्यूरो चीफ, उत्तरकाशी) 7376757899 वेबसाई- www.pathpravah.com